1 year round Sports and Fitness in villages to state model, in Rajasthan.

Rajasthan is also gearing up to establish a sporting culture throughout the year by the help of an ambitious project named Sports and Fitness for All which will make games available at the panchayat stage up to the state stage. Over 70 lakh players in 46,163 villages are predicted to attend. The project will identify talent in rural and urban Rajasthan and offer frequent competition opportunities rather than making sports an event that is seasonal in nature. Khelo Rajasthan has been provided with 50 crore by the State government and the programme comprises of both the traditional Indian games and the major Olympic disciplinary sports. This can be a significant grassroots sports development model of Rajasthan.

Some of the most important characteristics of Sports and Fitness for All are discussed.

- The programme will ensure Rajasthan plays all year round and all year long.
- The competitions will be undertaken between panchayat level to state level.
- The number of participants who are likely to participate is in excess of 70 lakh.
- It serves a rural outreach with 46163 village units addressed by the initiative.
- 50 crore have been given by the State government to the wider sports drive.
- The programme is a mixture of traditional games and the modern competitive sports.
- It is supposed to develop talent in the village to city to state.

Sports as part of the Programme.

- All in all, the programme consists of 12 sports.
- Conventional sports like Sitoliya, Kho-Kho and Tug of War have been incorporated.
- Other sporting activities are also represented by Athletics, Kabaddi, Football, Volleyball, wrestling, basketball, judo, and Archery.
- In the rural group, the predominant sporting activities are Athletics, Kabaddi, Football, Volleyball, Tug of War, Sitoliya, Kho-Kho and wrestling.
- In the urban category, all the major sports are Athletics, Kabaddi, Football, Volleyball, Tug of War, Sitoliya, Basketball and Judo.

Participation Structure at the different levels.

- Panchayat level: 152 players to a unit, 46,163 units, total -70,16,776 participants.
- Block level: 152 players to the unit, 11,341 units, overall number of participants is 17, 23, 832.
- Cluster level: 152 players/unit, 628 units, overall 95456 participants.
- District level: 304 players in a unit, 618 units, total 1,88,176 participants.
- State level: 222 players per unit, 41 units, total 9,102 participants.

There is a calendar of state-level competition that enables schools to compete at the state level.

- Kabaddi (Kota): 20 April -20 May
- Football (Jaipur): 20 April -20 May
- Archery and Wrestling (Jaipur): 1 June to 15 June.
- Volleyball (Jaipur): 1 July 31 July.
- Judo (Tonk) and another line of attack planned in Bharatpur: 15 August to 10 September.
- Tug of War (Udaipur) and Kho Kho (Ajmer): 1 October-30 October.
- Sitoliya (Bikaner) and Athletics (Jaipur): 15 November-15 December.

Importance for Rajasthan

Grassroots development of talents is another approach used by other organizations.

- It is possible to find sporting talent in remote villages with the help of the programme.
- It has the capability of narrowing the divide between rural and urban sporting opportunities.
- De facto regular competitions can also provide a path to district and state-level players.

RASonly

Social and Administrative Value:

- The model encourages the involvement of the population and the community.
- It assists in fitness, discipline and mobilisation of the youth.
- It is also an indication of administrative planning in terms of multi-level organisation and extensive coverage of the territory.

Conclusion

Sports and Fitness for All is not only a sports event but a grass root development exercise of Rajasthan. It can cover the villages, blocks and clusters, districts, and the state level and establish an enduring sports culture and introduce the untapped talent to the mainstream. Its size of participation and year-round structure can be considered an important event to the sports ecosystem of Rajasthan. Organized in uploaded format guide.

MCQs(RAS Prelims)

1. What is the primary goal of the Rajasthan initiative: Sports and Fitness for All?

(a) To arrange only city sport leagues in large cities.

(b) To establish a sports culture that is year-round, beginning at the panchayat to state.

(c) To substitute traditional games with Olympic competitions only.

(d) To restrict the participation to school going athletes.

Answer: (b)

Explanation : The project will help create a sustained sports culture in the state of Rajasthan by hosting panchayat-level competitions to the state level. It majors in extensive involvement, the discovery of talent and frequent sporting activity among the rural and urban areas.

2. Greater than the number of players who will be involved in this sports project in Rajasthan?

(a) 10 lakh

(b) 25 lakh

(c) 50 lakh

(d) 70 lakh

Answer: (d)

Explanation: The program will be conducted on an extremely massive scale and it is expected to involve more than 70 lakh players. This has made it one of the largest

RASonly

grass root sports participation in Rajasthan particularly as it cut across over 46,000 village units.

3. What type of sport would be considered as rural and not urban according to the given plan?

(a) Basketball

(b) Judo

(c) Kho-Kho

(d) Athletics

Answer: (c)

The Kho-Kho is specially mentioned in the rural category, whereas in the urban category there are Basketball and Judo mentioned instead. Athletics is shared across the two categories, which makes Kho-Kho the right choice among the provided options.

राजस्थान में गाँव से राज्य स्तर तक वर्षभर खेल और तंदुरुस्ती का मॉडल।

राजस्थान अब वर्षभर खेल संस्कृति विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके लिए **सभी के लिए खेल और तंदुरुस्ती** नामक एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक खेल प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएँगी। अनुमान है कि **46,163 गाँवों** से **70 लाख से अधिक खिलाड़ी** इसमें भाग लेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी राजस्थान में प्रतिभाओं की पहचान करना तथा खेलों को केवल मौसमी आयोजन न बनाकर नियमित प्रतिस्पर्धा का अवसर उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार ने **खेलो राजस्थान** के लिए **50 करोड़ रुपये** का प्रावधान किया है। इस कार्यक्रम में पारंपरिक भारतीय खेलों के साथ-साथ प्रमुख ओलंपिक खेलों को भी शामिल किया गया है। यह राजस्थान में जमीनी स्तर पर खेल विकास का एक महत्त्वपूर्ण मॉडल बन सकता है।

सभी के लिए खेल और तंदुरुस्ती की प्रमुख विशेषताएँ

- यह कार्यक्रम सुनिश्चित करेगा कि राजस्थान में खेलों का वातावरण पूरे वर्ष बना रहे।
- प्रतियोगिताएँ पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक आयोजित की जाएँगी।
- इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या **70 लाख से अधिक** रहने की संभावना है।

RASonly

- इस पहल के माध्यम से **46,163 गाँव इकाइयों** तक पहुँच बनाई जाएगी, जो व्यापक ग्रामीण विस्तार को दर्शाती है।
- राज्य सरकार ने व्यापक खेल अभियान के लिए **50 करोड़ रुपये** उपलब्ध कराए हैं।
- इस कार्यक्रम में पारंपरिक खेलों और आधुनिक प्रतिस्पर्धी खेलों का समन्वय किया गया है।
- इसका उद्देश्य गाँव से शहर और शहर से राज्य स्तर तक प्रतिभा को विकसित करना है।

कार्यक्रम में शामिल खेल

- कुल मिलाकर इस कार्यक्रम में **12 खेल** शामिल हैं।
- पारंपरिक खेलों में **सितोलिया**, **खो-खो** और **रस्साकशी** को शामिल किया गया है।
- अन्य खेलों में **एथलेटिक्स, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कुश्ती, बास्केटबॉल, जूडो और तीरंदाजी** सम्मिलित हैं।
- **ग्रामीण वर्ग** में प्रमुख खेल हैं — एथलेटिक्स, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, रस्साकशी, सितोलिया, खो-खो और कुश्ती।
- **शहरी वर्ग** में प्रमुख खेल हैं — एथलेटिक्स, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, रस्साकशी, सितोलिया, बास्केटबॉल और जूडो।

विभिन्न स्तरों पर भागीदारी संरचना

- **पंचायत स्तर:** प्रति इकाई 152 खिलाड़ी, 46,163 इकाइयाँ, कुल **70,16,776** प्रतिभागी।
- **ब्लॉक स्तर:** प्रति इकाई 152 खिलाड़ी, 11,341 इकाइयाँ, कुल **17,23,832** प्रतिभागी।
- **क्लस्टर स्तर:** प्रति इकाई 152 खिलाड़ी, 628 इकाइयाँ, कुल **95,456** प्रतिभागी।
- **जिला स्तर:** प्रति इकाई 304 खिलाड़ी, 618 इकाइयाँ, कुल **1,88,176** प्रतिभागी।
- **राज्य स्तर:** प्रति इकाई 222 खिलाड़ी, 41 इकाइयाँ, कुल **9,102** प्रतिभागी।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का कैलेंडर

- **कबड्डी (कोटा):** 20 अप्रैल से 20 मई
- **फुटबॉल (जयपुर):** 20 अप्रैल से 20 मई
- **तीरंदाजी और कुश्ती (जयपुर):** 1 जून से 15 जून
- **वॉलीबॉल (जयपुर):** 1 जुलाई से 31 जुलाई
- **जूडो (टोंक) तथा एक अन्य चरण भरतपुर में:** 15 अगस्त से 10 सितंबर
- **रस्साकशी (उदयपुर) और खो-खो (अजमेर):** 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर
- **सितोलिया (बीकानेर) और एथलेटिक्स (जयपुर):** 15 नवंबर से 15 दिसंबर

RASonly

राजस्थान के लिए महत्त्व

जमीनी स्तर पर प्रतिभा विकास

- इस कार्यक्रम की सहायता से दूरस्थ गाँवों में छिपी खेल प्रतिभाओं की पहचान की जा सकती है।
- यह ग्रामीण और शहरी खेल अवसरों के बीच की दूरी को कम करने की क्षमता रखता है।
- नियमित प्रतियोगिताएँ खिलाड़ियों को जिला और राज्य स्तर तक पहुँचने का मार्ग प्रदान कर सकती हैं।

सामाजिक और प्रशासनिक महत्त्व

- यह मॉडल जनभागीदारी और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देता है।
- यह तंदुरुस्ती, अनुशासन और युवाओं की सक्रिय भागीदारी को सुदृढ़ करता है।
- यह बहु-स्तरीय संगठन और व्यापक भौगोलिक कवरेज के माध्यम से प्रशासनिक योजना का भी संकेत देता है।

निष्कर्ष

सभी के लिए खेल और तंदुरुस्ती केवल एक खेल आयोजन नहीं है, बल्कि राजस्थान का एक जमीनी विकास अभियान है। यह गाँव, ब्लॉक, क्लस्टर, जिला और राज्य स्तर तक विस्तार पाकर स्थायी खेल संस्कृति विकसित कर सकता है तथा छिपी हुई प्रतिभाओं को मुख्यधारा में ला सकता है। इसकी विशाल भागीदारी और वर्षभर चलने वाली संरचना राजस्थान के खेल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक महत्त्वपूर्ण पहल सिद्ध हो सकती है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. राजस्थान की पहल 'सभी के लिए खेल और तंदुरुस्ती' का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(a) केवल बड़े शहरों में शहरी खेल लीग आयोजित करना।
(b) पंचायत से राज्य स्तर तक वर्षभर चलने वाली खेल संस्कृति स्थापित करना।
(c) पारंपरिक खेलों को हटाकर केवल ओलंपिक खेलों को रखना।
(d) भागीदारी को केवल विद्यालय जाने वाले खिलाड़ियों तक सीमित करना।

उत्तर: (b)
व्याख्या: इस कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्थान में स्थायी खेल संस्कृति विकसित करना है। इसके अंतर्गत पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएँगी। इसका मुख्य बल व्यापक भागीदारी, प्रतिभा की पहचान और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में नियमित खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने पर है।

2. राजस्थान की इस खेल परियोजना में अनुमानतः कितने से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे?
(a) 10 लाख
(b) 25 लाख

RASonly

(c) 50 लाख
(d) 70 लाख

उत्तर: (d)
व्याख्या: यह कार्यक्रम अत्यंत बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है और इसमें **70 लाख से अधिक खिलाड़ियों** की भागीदारी अपेक्षित है। विशेष रूप से यह पहल **46,000 से अधिक गाँव इकाइयों** को समेटती है, इसलिए यह राजस्थान के सबसे बड़े जमीनी खेल अभियानों में से एक मानी जा सकती है।

3. दिए गए कार्यक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा खेल ग्रामीण वर्ग में शामिल है, पर शहरी वर्ग में सूचीबद्ध नहीं है?
(a) बास्केटबॉल
(b) जूडो
(c) खो-खो
(d) एथलेटिक्स

उत्तर: (c)
व्याख्या: खो-खो का विशेष उल्लेख ग्रामीण वर्ग में किया गया है, जबकि शहरी वर्ग में उसकी जगह **बास्केटबॉल** और **जूडो** को शामिल किया गया है। **एथलेटिक्स** दोनों वर्गों में समान रूप से मौजूद है। इसलिए दिए गए विकल्पों में **खो-खो** सही उत्तर है

RASonly

The performance of Rajasthan in the 7th Senior Para badminton championship.

The para badminton team of Rajasthan managed to perform to a large extent at the 7th Senior Para Badminton Championship and Paralymic champion Krishna Nagar

brought about the best achievement with the collection of two gold medals. The individual excellence and good coordination in the doubles were evidenced in his winning both in the men singles SH6 category and the mixed doubles SH6 category. This success is a big milestone to Rajasthan since it shows the ever-increasing popularity of para sports in the State. Other players also won medals in the event making Rajasthan even more successful and demonstrating that the State is gradually accumulating depth and competitiveness in para badminton at the national level.

The performance of Double Gold by Krishna Nagar.

- Krishna Nagar became the winner of the SH6 men singles title.
- In the singles final he beat Sudarshan M.S. by 21-10, 21-19.
- He also played aggressively and showed great control throughout the match.
- This acted as a confirmation of his position as a top para badminton player in the country.

Second Gold in Mixed Doubles

- Krishna Nagar took his second gold medal in the SH6 mixed doubles event.
- he arranged with Nityashri Sumathi siwan in this classification.
- The two finally won by defeating Sudarshan M.S. and Shreya Kumari by 21-7, 21-11.
- The outcome showed a significant coordination and obvious dominance in the final.

Other Achievement of Rajasthan.

- Aryan Sharma is a winner of a gold medal in the SL4 men category.
- Kaushika Devda took the lead in the SU5 women doubles event where he won a bronze medal.
- B. Chetna has won the SH6 women doubles competition in the bronze medal.

These findings established that it was not just a single athlete who made Rajasthan successful at the championship.

Krishna Nagar's Response

Significance of the Victory

- In response, Krishna Nagar claimed that it is always special to win at least two titles at a national championship.
- He observed that India is an up and coming place in terms of the quality of para badminton.
- According to him, this increased standard encourages players to even take their performance to the next level.

RASonly

Future Competitions: Trust.

- He also said that this performance would provide him with confidence in the international events ahead.
- These wins boost the morale of a person and the sporting image of the State.

The presence of the institution facilitating and acknowledging the program.

- Data regarding the winners of Rajasthan medals was provided by the individual, namely, Himmat Singh of the Rajasthan Disabled Para Sports Association.
- All the winners of the medals were congratulated by the President, Rajbala Saini and Dronacharya Awardee Mahavir Saini.
- Their reaction shows increased awareness and support of para athletes in Rajasthan.

Conclusion

The performance of Rajasthan in the 7 th Senior Para Badminton Championship was excellent, profound, and bright. The two gold medals of Krishna Nagar were the main milestone whereas other medals winners contributed to the overall success of the State. The show emphasizes the growing popularity of Rajasthan in para badminton and it presents great prospects in hosting more national and international events in future.

MCQs(RAS Prelims)

1. Where did Krishna Nagar win two gold medals in the 7 th Senior Para Badminton Championship in?

(a) SH6 Men singles and mixed doubles.

(b) SL4 Men doubles, SU5 Mixed doubles.

(c) SL4 and SH6 At this point, each sport involves two or more athletes.

(d) Mixed doubles SU5 and singles WH1.

Answer: (a)

Explanation: Krishna Nagar became a gold winner in the men singles SH6 division and won the other gold in the mixed doubles SH6 event as well. These two wins propelled him to be the most popular Rajasthan player in the championship.

2. Who was beaten by Krishna Nagar in the men singles SH6 final?

(a) Aryan Sharma

RASonly

(b) Sudarshan M.S.

(c) Mahavir Saini

(d) Shreya Kumari

Answer: (b)

Explanation : Krishna Nagar overpowered Sudarshan M.S. in the men singles SH6 final by 21-10, 21-19. The game was indicative of his offensive ways and good command of the field.

3. What athlete of Rajasthan won a gold medal at the same championship in the SL4 men category?

(a) Kaushika Devda

(b) B. Chetna

(c) Aryan Sharma

(d) Himmat Singh

Answer: (c)

Explanation : Aryan Sharma won a gold medal at SL4 men category which contributed to the success of Rajasthan. This was displayed in his medal, which indicated that the success of Rajasthan in the championship was not restricted to the double-gold performance of Krishna Nagar.

7वीं वरिष्ठ पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रदर्शन।

राजस्थान की पैरा बैडमिंटन टीम ने **7वीं वरिष्ठ पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता** में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में **पैरालंपिक चैम्पियन कृष्णा नागर** सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में सामने आए, जिन्होंने **दो स्वर्ण पदक** जीते। उन्होंने **पुरुष एकल एसएच-6 वर्ग** तथा **मिश्रित युगल एसएच-6 वर्ग** में स्वर्ण पदक प्राप्त कर व्यक्तिगत उत्कृष्टता और युगल समन्वय दोनों का अवलोकन दिया। यह सफलता राजस्थान के लिए विशेष महत्त्व रखती है क्योंकि यह राज्य में पैरा खेलों की बढ़ती सशक्त उपस्थिति को दर्शाती है। प्रतियोगिता में अन्य खिलाड़ियों ने भी पदक जीतकर राजस्थान की उपलब्धि को और मजबूत किया, जिससे स्पष्ट होता है कि राज्य राष्ट्रीय स्तर पर पैरा बैडमिंटन में गहराई और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकसित कर रहा है।

कृष्णा नागर का दोहरा स्वर्ण प्रदर्शन

- कृष्णा नागर ने **पुरुष एकल एसएच-6 वर्ग** का खिताब जीता।
- एकल फाइनल में उन्होंने **सुदर्शन एम.एस.** को **21-10, 21-19** से हराया।

RASonly

- पूरे मुकाबले में उन्होंने आक्रामक खेल और उत्कृष्ट नियंत्रण का प्रदर्शन किया।
- इस प्रदर्शन ने देश के शीर्ष पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों में उनकी स्थिति को और मजबूत किया।

मिश्रित युगल में दूसरा स्वर्ण

- कृष्णा नागर ने अपना **दूसरा स्वर्ण पदक मिश्रित युगल एसएच-6 वर्ग** में जीता।
- इस वर्ग में उनकी जोड़ी **नित्याश्री सिवन** के साथ बनी।
- फाइनल में इस जोड़ी ने **सुदर्शन एम.एस.** और **श्रेया कुमारी** को **21-7, 21-11** से पराजित किया।
- इस जीत ने दोनों खिलाड़ियों के बेहतर तालमेल और स्पष्ट वर्चस्व को प्रदर्शित किया।

राजस्थान की अन्य उपलब्धियाँ

- **आर्यन शर्मा** ने **पुरुष एसएल-4 वर्ग** में **स्वर्ण पदक** जीता।
- **कौशिका देवड़ा** ने **महिला युगल एसयू-5 वर्ग** में **कांस्य पदक** प्राप्त किया।
- **बी. चेतना** ने **महिला युगल एसएच-6 वर्ग** में **कांस्य पदक** जीता।
- इन उपलब्धियों से स्पष्ट हुआ कि प्रतियोगिता में राजस्थान की सफलता केवल एक खिलाड़ी तक सीमित नहीं रही।

कृष्णा नागर की प्रतिक्रिया

विजय का महत्त्व

- कृष्णा नागर ने कहा कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में **दो खिताब जीतना** हमेशा विशेष अनुभव होता है।
- उन्होंने बताया कि भारत में **पैरा बैडमिंटन का स्तर** लगातार बेहतर हो रहा है।
- उनके अनुसार, यह बढ़ता हुआ स्तर खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन को और ऊँचा उठाने के लिए प्रेरित करता है।

भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए विश्वास

- उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रदर्शन उन्हें आगामी **अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं** के लिए आत्मविश्वास प्रदान करेगा।
- ऐसी जीतें खिलाड़ी के मनोबल के साथ-साथ राज्य की खेल छवि को भी मजबूत करती हैं।

संस्थागत सहयोग और सम्मान

- राजस्थान के पदक विजेताओं की जानकारी **राजस्थान दिव्यांग पैरा खेल संघ** के **हिम्मत सिंह** द्वारा दी गई।
- सभी पदक विजेताओं को **अध्यक्ष राजबाला सैनी** तथा **द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता महावीर सैनी** ने बधाई दी।

RASonly

- उनकी प्रतिक्रिया राजस्थान में पैरा खिलाड़ियों के प्रति बढ़ती जागरूकता और समर्थन को दर्शाती है।

निष्कर्ष

7वीं वरिष्ठ पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रदर्शन उत्कृष्ट, प्रभावशाली और आशाजनक रहा। कृष्णा नागर के दो स्वर्ण पदक इस सफलता की सबसे बड़ी उपलब्धि रहे, जबकि अन्य पदक विजेताओं ने राज्य की समग्र उपलब्धि को और सशक्त बनाया। यह प्रदर्शन पैरा बैडमिंटन में राजस्थान की बढ़ती पहचान को रेखांकित करता है और भविष्य में राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अधिक सफलता की संभावनाएँ प्रस्तुत करता है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. कृष्णा नागर ने 7वीं वरिष्ठ पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में किन स्पर्धाओं में दो स्वर्ण पदक जीते?
(a) पुरुष एकल एसएच-6 और मिश्रित युगल एसएच-6
(b) पुरुष युगल एसएल-4 और मिश्रित युगल एसयू-5
(c) पुरुष एकल एसएल-4 और पुरुष युगल एसएच-6
(d) मिश्रित युगल एसयू-5 और एकल डब्ल्यूएच-1

उत्तर: (a)
व्याख्या: कृष्णा नागर ने पुरुष एकल एसएच-6 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और इसके साथ ही मिश्रित युगल एसएच-6 वर्ग में भी दूसरा स्वर्ण हासिल किया। इन दोनों जीतों ने उन्हें प्रतियोगिता में राजस्थान का सबसे प्रमुख प्रदर्शनकर्ता बना दिया।

2. पुरुष एकल एसएच-6 फाइनल में कृष्णा नागर ने किस खिलाड़ी को हराया?
(a) आर्यन शर्मा
(b) सुदर्शन एम.एस.
(c) महावीर सैनी
(d) श्रेया कुमारी

उत्तर: (b)
व्याख्या: कृष्णा नागर ने पुरुष एकल एसएच-6 फाइनल में सुदर्शन एम.एस. को 21-10, 21-19 से पराजित किया। यह मुकाबला उनके आक्रामक खेल, मजबूत नियंत्रण और उच्च स्तरीय तैयारी का स्पष्ट प्रमाण था।

3. उसी प्रतियोगिता में पुरुष एसएल-4 वर्ग में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता?
(a) कौशिका देवड़ा
(b) बी. चेतना
(c) आर्यन शर्मा
(d) हिम्मत सिंह

उत्तर: (c)
व्याख्या: आर्यन शर्मा ने पुरुष एसएल-4 वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर राजस्थान की सफलता में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। उनके पदक ने यह सिद्ध किया कि प्रतियोगिता में राज्य की उपलब्धि केवल कृष्णा नागर के दोहरे स्वर्ण तक सीमित नहीं थी।

RASonly

Rajasthan Municipalities (Amendment) Bill, 2026 and its impact on the elections to the local bodies in the cities.

The Rajasthan Legislature assembly has voted in support of the Rajasthan Municipalities (Amendment) Bill, 2026. The amendment is a significant reform in the eligibility provisions of the elections of urban local bodies in that a candidate who bore more than two children can contest. Such candidates used to be banned earlier to deter the uncontrolled increase of population. The Urban Development Minister has said that the evolving social situation and rise in awareness among the people rendered the previous restriction less pertinent. The amendment also withdraws the list of dangerous diseases in the rajasthan Municipalities Act, 2009 as per the concepts of non-discrimination and a Supreme Court order of the list of dangerous diseases. The urban governance is important in terms of democratic participation and inclusive representation.

The key provisions of the Amendment.

The two-child disqualification will be eliminated.

- Candidates possessing over two children shall now be in a position to challenge the elections to the urban local bodies in Rajasthan.
- The previous limit had been implemented to ensure uncontrolled increase in population.

- The State government now believes that rule to be obsolete in the new social environment.
- The amendment has been put forward as a move according to the spirit of democracy of broader participation.
- It is supposed to empower the entry of the urban local bodies by the electoral process through experienced persons.

Elimination of Leprosy on Disqualification Platform.

- The amendment repeals the list of dangerous diseases as defined in the Rajasthan Municipalities Act, 2009 in the category of leprosy.
- This has been done to make sure that those that are or have been treated as a result of leprosy are not discriminated.
- The Minister claimed that the decision has been made in response to a Supreme Court order.

Causes of Urban Local Body Elections Delays.

Population Data Issue, OBC Reservation.

- According to the Minister, the elections to the urban local bodies are postponed due to the lack of official data on the population of OBC.
- The problem is connected with the court instructions on provision of political reservation to Other Backward Classes.
- The Supreme Court has stated that the State OBC Commission is obliged to give the State government the authorised population data.
- Only on the condition of such data allowance can be given to OBCs.
- The government has been indicating that it desires to make sure that there is proper representation of OBCs in urban local bodies, through reservation.

The Urban Local Bodies are delimited.

Status of Ward Delimitation

- The State government declared that urban local bodies were being delimited based on the fixed norms and standards.
- Out of the total number of urban local bodies of the state, totaling to 309, 234 have been delimited in full as per the prescribed standard.
- In other urban local bodies, it is only with minimal deviation that there has been occurrence.
- There is the power of delimitation and determination of boundaries as per the Rajasthan Municipalities Act under Section 10.

RASonly

Judicial Position

- With reference to delimitation, there were four writ petitions with reference to three local urban bodies.
- They are the recent decisions by the Division Bench of the High Court that supported the restructuring of wards as a valid decision.
- This assists the State government position in delimitation matters.

Voter List and Election Preparation:

- Preparation of the voter list is under the jurisdiction of the Election Commission.
- The last figures of the special intensive revision (SIR) will require four to six months, according to the State Election Commission.
- Thus, the existing voter list has been drawn up on the basis of the available data.

- The annual yearly reports and accounts will include administrative clarifications, as will the scheme of operations

Action Against Corruption

- The department has mentioned that it will take a stringent measure against any employee who has engaged in corruption.
- This is the case with Development Funds, which have several conditions.
- It has been made clear that a development work is only allowed to be approved with funds of MP/MLA Local Area Development when there is land in the revenue record.

Conclusion

The enactment of the Rajasthan Municipalities (Amendment) Bill, 2026 is a significant shift in the urban governance system of Rajasthan. The amendment increases access to democracy and promotes inclusion by eliminating the two-child disqualification and discrimination associated with leprosy. Meanwhile, the debate in the Assembly indicated systematic problems like OBC reservation data, delimitation, revision of the voter list and administrative responsibility. These developments are significant together in knowing the current position of the urban local body elections in Rajasthan.

MCQs(RAS Prelims)

1. What are some of the changes that have been introduced by the Rajasthan Municipalities (Amendment) Bill, 2026?

(a) OBC reservation in urban local bodies has been abolished.

RASonly

(b) Urban local body elections can now be contested by the candidates who have over two children.

(c) The High Court has been given power of delimitation.

(d) Authority has been vested on the Election Commission to amend the Act.

Answer: (b)

Explanation: The Rajasthan Municipalities (Amendment) Bill, 2026 enables a candidate to run elections at the urban local bodies provided he or she has over two children. Previously, these candidates were not allowed to be in the race. The government claimed that the previous rule was no longer relevant in the new social environment and its abolishment is in line with democratic participation.

2. Why not the urban local body elections in Rajasthan to be held as the discussion in the Assembly suggests?

(a) The reason is that delimitation has been cancelled

(b) Since the State Election Commission declined to prepare lists of voters.

(c) Since there is no official OBC population data available to make a political reservation.

(d) Owing to the fact that the Rajasthan Municipalities Act, 2009 has expired.

Answer: (c)

Explanation The Minister said the electoral commission was postponing elections in urban local bodies since official information on the population of OBC was not available. The Supreme Court has made it mandatory that State OBC Commission provide approved population figures before political reservation of the OBCs could be given in local bodies elections.

3. What disease was excluded in the category of dangerous diseases under the Rajasthan Municipalities Act, 2009 by the amendment?

(a) Tuberculosis

(b) Smallpox

(c) Leprosy

(d) Cholera

Answer: (c)

Rationalization: The amendment takes off the list of hazardous diseases of the Rajasthan Municipalities Act, 2009, leprosy. It was done to stop discrimination

RASonly

against individuals with the leprosy or subjected to leprosy treatment and was reported to be in accordance with an order of the Supreme Court.

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 और नगरीय निकाय चुनावों पर उसका प्रभाव।

राजस्थान विधानसभा ने **राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026** को पारित कर दिया है। यह संशोधन नगरीय निकाय चुनावों की पात्रता व्यवस्था में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाता है, क्योंकि अब **दो से अधिक संतान वाले प्रत्याशी** भी चुनाव लड़ सकेंगे। पहले ऐसे प्रत्याशियों पर रोक थी, जिसका उद्देश्य अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि को रोकना था। नगरीय विकास मंत्री के अनुसार बदली हुई सामाजिक परिस्थितियों और आमजन में बढ़ी जागरूकता के कारण यह पुराना प्रतिबंध अब कम प्रासंगिक हो गया है। संशोधन के माध्यम से **राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009** में परिभाषित खतरनाक रोगों की सूची से **कुष्ठ रोग** को भी हटा दिया गया है, ताकि इससे प्रभावित या उपचारित व्यक्तियों के साथ भेदभाव न हो। यह परिवर्तन नगरीय शासन में लोकतांत्रिक भागीदारी और समावेशी प्रतिनिधित्व की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

संशोधन के प्रमुख प्रावधान

दो-संतान अयोग्यता का अंत

- अब **दो से अधिक संतान वाले प्रत्याशी** राजस्थान के **नगरीय निकाय चुनावों** में भाग ले सकेंगे।
- पहले यह प्रतिबंध अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से लगाया गया था।
- राज्य सरकार का मानना है कि वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में यह नियम अब **अप्रासंगिक** हो गया है।
- इस संशोधन को **विस्तृत लोकतांत्रिक भागीदारी** की भावना के अनुरूप प्रस्तुत किया गया है।
- इससे **अनुभवी व्यक्तियों** को भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से नगरीय निकायों में आने का अवसर मिलेगा।

कुष्ठ रोग को अयोग्यता ढाँचे से बाहर करना

- संशोधन के तहत **राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009** में परिभाषित **खतरनाक रोगों** की सूची से **कुष्ठ रोग** को हटा दिया गया है।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कुष्ठ रोग से प्रभावित या उपचारित व्यक्तियों के साथ **भेदभाव** न हो।
- मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय **सर्वोच्च न्यायालय के आदेश** की पालना में लिया गया है।

RASonly

नगरीय निकाय चुनावों में देरी के कारण

अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण और जनसंख्या आँकड़ों का प्रश्न

- मंत्री के अनुसार **नगरीय निकाय चुनावों में देरी** का मुख्य कारण **अन्य पिछड़ा वर्ग की आधिकारिक जनसंख्या का अभाव** है।
- यह विषय **अन्य पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक आरक्षण** देने से जुड़ा हुआ है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि **राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग** को अधिकृत जनसंख्या आँकड़े राज्य सरकार को उपलब्ध कराने होंगे।
- राज्य सरकार द्वारा इन आँकड़ों की स्वीकृति के बाद ही **राजनीतिक आरक्षण** प्रदान किया जा सकेगा।
- सरकार ने कहा है कि वह नगरीय निकायों में **अन्य पिछड़ा वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व** सुनिश्चित करना चाहती है।

नगरीय निकायों का परिसीमन

वार्ड परिसीमन की स्थिति

- राज्य सरकार ने कहा कि नगरीय निकायों का परिसीमन **निर्धारित मानकों और मापदंडों** के अनुसार किया जा रहा है।
- राज्य के **309 नगरीय निकायों** में से 234 में परिसीमन पूरी तरह निर्धारित मानकों के अनुरूप किया गया है।
- शेष निकायों में केवल **न्यूनतम विचलन** हुआ है।
- **राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 10** के अंतर्गत राज्य सरकार को **सीमांकन और परिसीमन** का अधिकार प्राप्त है।

न्यायिक स्थिति

- परिसीमन से संबंधित **तीन नगरीय निकायों** के संबंध में **चार रिट याचिकाएँ** दायर की गई थीं।
- हाल ही में **उच्च न्यायालय की खंडपीठ** ने **वार्डों के पुनर्गठन** को उचित ठहराया है।
- इससे परिसीमन के मामले में राज्य सरकार की स्थिति को विधिक समर्थन मिला है।

मतदाता सूची और चुनाव तैयारी

- **मतदाता सूची तैयार करने का अधिकार** निर्वाचन आयोग के पास है।
- राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार **विशेष गहन पुनरीक्षण** के अंतिम आँकड़े आने में **चार से छह महीने** लगेंगे।
- इसलिए वर्तमान मतदाता सूची **उपलब्ध आँकड़ों** के आधार पर तैयार की गई है।

RASonly

प्रशासनिक स्पष्टीकरण

भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई

- विभाग ने स्पष्ट किया है कि **भ्रष्टाचार में लिप्त कार्मिकों** के विरुद्ध **कठोर कार्रवाई** की जाएगी।

विकास निधि से संबंधित शर्त

- यह भी स्पष्ट किया गया कि **सांसद या विधायक क्षेत्रीय विकास निधि** से किसी विकास कार्य के लिए राशि तभी स्वीकृत होगी जब उसके लिए **राजस्व अभिलेख में भूमि उपलब्ध** हो।

निष्कर्ष

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 राजस्थान की नगरीय शासन व्यवस्था में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। दो-संतान अयोग्यता को समाप्त कर तथा कुष्ठ रोग से जुड़े भेदभाव को हटाकर इस संशोधन ने लोकतांत्रिक भागीदारी को अधिक व्यापक और समावेशी बनाया है। साथ ही विधानसभा में हुई चर्चा ने यह भी स्पष्ट किया कि अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण, परिसीमन, मतदाता सूची पुनरीक्षण और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे मुद्दे नगरीय निकाय चुनावों की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 द्वारा निम्न में से कौन-सा परिवर्तन किया गया है?

(a) नगरीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है।
(b) दो से अधिक संतान वाले प्रत्याशी अब नगरीय निकाय चुनाव लड़ सकेंगे।
(c) परिसीमन की शक्ति उच्च न्यायालय को दे दी गई है।
(d) निर्वाचन आयोग को अधिनियम संशोधित करने का अधिकार दे दिया गया है।

उत्तर: (b)
व्याख्या: राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत अब दो से अधिक संतान वाले प्रत्याशी भी नगरीय निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। पहले ऐसे प्रत्याशी अयोग्य माने जाते थे। राज्य सरकार ने माना कि बदली हुई सामाजिक परिस्थितियों में यह प्रतिबंध अब अप्रासंगिक हो गया है और इसका हटाया जाना लोकतांत्रिक भागीदारी की भावना के अनुरूप है।

2. विधानसभा में हुई चर्चा के अनुसार राजस्थान में नगरीय निकाय चुनावों में देरी का प्रमुख कारण क्या है?

(a) परिसीमन की प्रक्रिया पूरी तरह रद्द कर दी गई है।
(b) राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची बनाने से इंकार कर दिया है।
(c) अन्य पिछड़ा वर्ग की आधिकारिक जनसंख्या के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
(d) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 समाप्त हो गया है।

उत्तर: (c)
व्याख्या: मंत्री ने कहा कि नगरीय निकाय चुनावों में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग

RASonly

की आधिकारिक जनसंख्या के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अधिकृत आँकड़े राज्य सरकार को उपलब्ध कराने होंगे, तभी राजनीतिक आरक्षण दिया जा सकेगा।

3. संशोधन के द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की खतरनाक रोगों की सूची से किस रोग को हटाया गया है?

(a) क्षय रोग
(b) चेचक
(c) कुष्ठ रोग
(d) हैजा

उत्तर: (c)
व्याख्या: संशोधन के माध्यम से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में परिभाषित खतरनाक रोगों की सूची से कुष्ठ रोग को बाहर किया गया है। इसका उद्देश्य कुष्ठ रोग से प्रभावित या उपचारित व्यक्तियों के साथ भेदभाव को समाप्त करना है। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना में लिया गया है।

only

Seeking to set up Maharana Pratap Sports University in Amer, Jaipur.

The Rajasthan Legislative Assembly has passed the voice vote Maharana Pratap Sports University, Jaipur Bill, 2025, which is the way to start a major sports university at Amer in Jaipur. Approximately, 2 lakh square metres of land has already been located and the construction of the walls has already commenced. It is anticipated that the project is going to incur a cost of over 101 crore. The university is supposed to boost education, training and research on physical education and sports besides

equip coaches and sports professionals and other professionals in the sports field. It will be a significant institutional move towards the long-term sports development and support system of athletes in Rajasthan.

The University has certain major characteristics that distinguish it.

- The university will be located at Amer, Jaipur.
- The project has been identified to have approximately 2 lakh square metres of land.
- The building of the boundary wall has already begun.
- Estimation cost of establishment is above the 101 crore.
- In the Assembly the Bill for its establishment was passed by voice vote.
- The university announcement had been covered in the 2024-25 Budget.

The university will promote the study, training, and innovation in various sports related areas, such as:

- School of Sports Sciences
- School of Sports Coaching
- School of Physical Education.
- School of Sports Medicine
- School of Sports Management
- School of Sports Technology
- School of Adventure Sports

It will also assist the students and trainees to develop careers in:

- Biomechanics
- Physiotherapy
- Sports Psychology
- Data Analysis
- Sports Medicine
- Nutrition Science

Role Statewide Jurisdiction and Affiliation.

- The University will have the jurisdiction of the whole State of Rajasthan.
- On the one hand, sports colleges opened in the State will have an opportunity to be affiliated to this university.
- First, it will have a provision of affiliateion of one sports college of each division.

The university will be in a position to affiliate:

- Practical education colleges of the State notified by the Government.

RASonly

- Sports schools and other institutions.
- Government sports colleges
- Private sports colleges
- Other qualified sports institutions.

Significance in Policy and Sports Development.

- It is likely that the university will foster education, training, and research in physical education and sports.
- It will assist in the creation of coaches and sports specialists who are trained.
- It will likely be in line with the goals of the National Education Policy and the Khelo Bharat policy framework.
- It will offer organized counseling to youth who are interested in a career in sports.

Governance Structure

Management Board

The chairmanship of the Vice-Chancellor will be a body of Managements called a Management Board.

It will comprise of ex-officio members like:

- Principal Secretaries to the Secretary of Finance, Higher Education, School Education and Medical Education.
- Chairman of the State Sports Council of Rajasthan state.
- Physical Education directorate, University of Rajasthan.
- Pro-Vice-Chancellor
- Member Secretary Registrar of the university .

It will have also nominated members who will include:

- One of the nominees of the Chancellor is an educationist.
- Two university professors
- Two successful and sporting icons.
- Other nominated members

Advisory Council

The university will also be comprised of an Advisory Council.

It will include:

- A Chairperson is a nationally recognized person who has been appointed by the Chancellor.
- Vice-Chancellor
- Principal Secretary Youth Affairs and Sports Department.

RASonly

- Chairman of Rajasthan State Sports Council or nominee.
- Executive director of Netaji Subhas National Institute of Sports, Netaji, Patiala.
- There are two outstanding players who are referees or umpires of international sports.
- The five players who have played in the Olympics or the World Championships representing India.
- Arjuna Award, Dronacharya Award, Guru Vashishtha Award, or Maharana Pratap Award two awardees of these awards
- Dean of Physiotherapy Faculty, Rajasthan University of Health Sciences, Rajasthan University of Health Sciences, R.
- Member Secretary- Registrar of Maharana Pratap Sports University as

Enhancing Infrastructure of Coaching.

- Approximately, it will involve the recruitment of around 150 permanent sports coaches in the Rajasthan State Sports council.
- There will also be employees, who will work on a temporary basis; namely, coaches (700).
- This is in the view of giving improved sports training to athletes within the State.
- Jagatpura has adopted the shooting range of RIICO.
- The government will encourage sports even more with the help of CSR support and other possibilities.

Medal Performance and Sports Vision are other competitors in the same category as CAMTR.

The Minister underscored the rise in sports culture in India and sports infrastructure development, as well as the growth in medals:

- Asian Games 2014: 57 medals
- Asian Games 2018: 69 medals
- Asian Games 2023: 107 medals

He also referred to the increase in the number of the medals since:

- Rio Para Olympics 2016: 4 medals
- Tokyo: 19 medals
- Paris 2024: 29 medals

The State government has also shown its intentions to guarantee the State a great representation in the 2036 Olympics with the athletes of the State issuing pride to the nation.

RASonly

Conclusion

The creation of a new sports university at Amer named Maharana Pratap Sports University is yet another significant move in the strategy of developing sports in Rajasthan. The university has special schools of sports science, coaching, medicine, technology and management that will bring about a total sports ecosystem in the State. It is a significant institutional change because of its statewide jurisdiction, authority over affiliation, and organization of governance and orientation to coaching recruitment. It could strengthen in the long run athlete preparation, sports education and the contribution of Rajasthan to nation and international sport success.

MCQs(RAS Prelims)

1. In which state in Rajasthan will Maharana Pratap Sports University be located?

(a) Jagatpura

(b) Udaipur

(c) Amer, Jaipur

(d) Kota

Answer: (c)

Explanation : Maharana Pratap Sports University will be set up at Amer in Jaipur. Already, some 2 lakh square metres of land has been identified in that area and the construction of boundary walls has begun. It is also considered as a location as it will be a major sports education, training, and research center in Rajasthan.

2. What is rightly identified with Maharana Pratap Sports University?

(a) It will be operating in Jaipur district only

(b) It will exercise jurisdiction over the whole State.

(c) It will not franchise any sports colleges.

(d) It will be restricted just to physical education training.

Answer: (b)

Explanation: This will be the State of all the Rajasthan under the university. It will also affiliate sport colleges, academies and other related institutions. Its contribution is more than mere physical education as it will be used to aid sports science, coaching, medicine, management, technology and other specialised fields that are related to careers in sports.

RASonly

3. In the Rajasthan State Sports Council, how many permanent coaches (in sports) are offered to be recruited?

(a) 50

(b) 100

(c) 150

(d) 700

Answer: (c)

Explanation: The government has been proposing engagement of approximately 150 permanent coaches of sports in the Rajasthan State Sports Council. Also, temporary employment of 700 coaches will be hired. This move is aimed at enhancing the quality of training of athletes and the sports infrastructure and preparation system in Rajasthan.

जयपुर के आमेर में महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना।

राजस्थान विधानसभा ने **महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2025** को ध्वनिमत से पारित कर दिया है, जिससे जयपुर के **आमेर** में एक प्रमुख खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसके लिए लगभग **2 लाख वर्ग मीटर भूमि** पहले ही चिन्हित की जा चुकी है और **चारदीवारी निर्माण** का कार्य भी प्रारम्भ हो चुका है। इस परियोजना पर **101 करोड़ रुपये से अधिक** की लागत आने का अनुमान है। यह विश्वविद्यालय शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देगा, साथ ही प्रशिक्षकों, खेल विशेषज्ञों और खेल क्षेत्र से जुड़े अन्य पेशेवरों को तैयार करेगा। यह राजस्थान में दीर्घकालिक खेल विकास और खिलाड़ियों के समर्थन तंत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण संस्थागत कदम सिद्ध होगा।

विश्वविद्यालय की प्रमुख विशेषताएँ

- विश्वविद्यालय की स्थापना **आमेर, जयपुर** में की जाएगी।
- परियोजना के लिए लगभग **2 लाख वर्ग मीटर भूमि** चिन्हित की गई है।
- **चारदीवारी का निर्माण** पहले ही प्रारम्भ हो चुका है।
- स्थापना पर **101 करोड़ रुपये से अधिक** व्यय होने का अनुमान है।
- इसके गठन से संबंधित विधेयक विधानसभा में **ध्वनिमत** से पारित हुआ।
- इस विश्वविद्यालय की घोषणा **वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट** में की गई थी।

RASonly

शैक्षणिक और प्रशिक्षण संरचना

यह विश्वविद्यालय खेलों से संबंधित अनेक क्षेत्रों में अध्ययन, प्रशिक्षण और नवाचार को प्रोत्साहित करेगा, जैसे:

- **खेल विज्ञान विद्यालय**
- **खेल प्रशिक्षक विद्यालय**
- **शारीरिक शिक्षा विद्यालय**
- **खेल चिकित्सा विद्यालय**
- **खेल प्रबंधन विद्यालय**
- **खेल प्रौद्योगिकी विद्यालय**
- **साहसिक खेल विद्यालय**

यह विद्यार्थियों और प्रशिक्षुओं को निम्न क्षेत्रों में कॅरियर निर्माण में भी सहायता देगा:

- **जैव-यांत्रिकी**
- **भौतिक चिकित्सा**
- **खेल मनोविज्ञान**
- **आँकड़ा विश्लेषण**
- **खेल चिकित्सा**
- **पोषण विज्ञान**

राज्यव्यापी अधिकार क्षेत्र और संबद्धता की भूमिका

- विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र **सम्पूर्ण राजस्थान राज्य** में होगा।
- राज्य में स्थापित होने वाले खेल महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय से **संबद्ध** हो सकेंगे।
- प्रारम्भ में प्रत्येक सम्भाग से **एक खेल महाविद्यालय** को संबद्ध करने का प्रावधान किया गया है।
- विश्वविद्यालय निम्न संस्थानों को संबद्ध कर सकेगा:
    - राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित **शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय**
    - **खेल अकादमियाँ** और संबंधित संस्थान
    - **राजकीय खेल महाविद्यालय**
    - **निजी खेल महाविद्यालय**
    - अन्य पात्र खेल संस्थान

RASonly

नीति और खेल विकास में महत्त्व

- विश्वविद्यालय शारीरिक शिक्षा और खेलकूद में **शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान** को बढ़ावा देगा।
- यह **प्रशिक्षित खेल प्रशिक्षकों और खेल विशेषज्ञों** के निर्माण में सहायक होगा।
- यह **राष्ट्रीय शिक्षा नीति** और **खेलो भारत नीति** के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा।
- यह खेलों में कॅरियर बनाने के इच्छुक युवाओं को **संगठित दिशा और मार्गदर्शन** प्रदान करेगा।

शासन संरचना

प्रबंध बोर्ड

विश्वविद्यालय में **कुलगुरु** की अध्यक्षता में एक **प्रबंध बोर्ड** गठित होगा। इसमें पदेन सदस्य के रूप में शामिल होंगे:

- **वित्त**, **उच्च शिक्षा**, **विद्यालय शिक्षा** और **चिकित्सा शिक्षा** के प्रमुख शासन सचिव
- **राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद** के अध्यक्ष
- **राजस्थान विश्वविद्यालय** के शारीरिक शिक्षा निदेशक
- **प्रतिकुलगुरु**
- विश्वविद्यालय के **कुल सचिव**, जो **सदस्य सचिव** होंगे

इसके अतिरिक्त इसमें नामित सदस्य भी होंगे, जैसे:

- **कुलाधिपति** द्वारा नामित एक शिक्षाविद्
- दो विश्वविद्यालयों के **आचार्य**
- दो **पुरस्कृत खिलाड़ी**
- अन्य नामित सदस्य

सलाहकार परिषद

विश्वविद्यालय के लिए एक **सलाहकार परिषद** का भी गठन किया जाएगा। इसमें शामिल होंगे:

- **कुलाधिपति** द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति, जो परिषद के अध्यक्ष होंगे
- **कुलगुरु**
- युवा मामले एवं खेल विभाग के **प्रमुख शासन सचिव**
- राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के **अध्यक्ष** या उनका नामित प्रतिनिधि
- **नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, पटियाला** के कार्यकारी निदेशक
- अंतरराष्ट्रीय खेलों में **रेफरी** या **अम्पायर** के रूप में मान्यता प्राप्त दो प्रमुख खिलाड़ी

RASonly

- **ओलम्पिक** या **विश्व चैम्पियनशिप** में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पाँच खिलाड़ी
- **अर्जुन पुरस्कार**, **द्रोणाचार्य पुरस्कार**, **गुरु वशिष्ठ पुरस्कार** या **महाराणा प्रताप पुरस्कार** प्राप्त दो खिलाड़ी
- **राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय** के भौतिक चिकित्सा संकायाध्यक्ष
- महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय के **कुल सचिव**, जो **सदस्य सचिव** होंगे

प्रशिक्षण अवसंरचना को सुदृढ़ करना

- **राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद** में लगभग **150 स्थायी खेल प्रशिक्षकों** की भर्ती की जाएगी।
- इसके अतिरिक्त **700 प्रशिक्षकों** को **अस्थायी आधार** पर लगाया जाएगा।
- इसका उद्देश्य राज्यभर के खिलाड़ियों को बेहतर खेल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है।
- **जगतपुरा स्थित निशानेबाजी परिसर** को **रीको** ने अपनाया है।
- सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए **निगमित सामाजिक दायित्व** और अन्य माध्यमों का उपयोग करेगी।

पदक प्रदर्शन और खेल दृष्टि

मंत्री ने भारत में खेल संस्कृति के बढ़ते प्रभाव और खेल अवसंरचना में सुधार के साथ पदकों की संख्या में वृद्धि का उल्लेख किया:

- **एशियाई खेल 2014:** 57 पदक
- **एशियाई खेल 2018:** 69 पदक
- **एशियाई खेल 2023:** 107 पदक

उन्होंने निम्न प्रतियोगिताओं में पदक संख्या वृद्धि का भी उल्लेख किया:

- **रियो पैरा ओलम्पिक 2016:** 4 पदक
- **टोक्यो:** 19 पदक
- **पेरिस 2024:** 29 पदक

राज्य सरकार ने यह संकल्प भी व्यक्त किया है कि **ओलम्पिक 2036** में राजस्थान का उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व हो और राज्य के खिलाड़ी देश का गौरव बढ़ाएँ।

निष्कर्ष

आमेर में **महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय** की स्थापना राजस्थान की खेल विकास रणनीति में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। खेल विज्ञान, प्रशिक्षण, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के लिए पृथक विद्यालयों के माध्यम से यह विश्वविद्यालय राज्य में एक समग्र खेल पारितंत्र विकसित करेगा। इसका राज्यव्यापी अधिकार क्षेत्र, संबद्धता की शक्ति, सुव्यवस्थित शासन ढाँचा तथा प्रशिक्षकों की भर्ती पर बल इसे एक महत्त्वपूर्ण संस्थागत सुधार बनाते हैं। दीर्घकाल में यह खिलाड़ियों की तैयारी, खेल शिक्षा और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के योगदान को सशक्त कर सकता है।

RASonly

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. राजस्थान में महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा?
(a) जगतपुरा
(b) उदयपुर
(c) आमेर, जयपुर
(d) कोटा

उत्तर: (c)
व्याख्या: महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना जयपुर के आमेर में की जाएगी। वहाँ लगभग 2 लाख वर्ग मीटर भूमि चिन्हित की जा चुकी है और चारदीवारी निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो गया है। यह स्थान महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह राजस्थान में खेल शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है।

2. निम्नलिखित में से महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय के बारे में कौन-सा कथन सही है?
(a) इसका कार्यक्षेत्र केवल जयपुर जिले तक सीमित रहेगा।
(b) इसका अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण राज्य पर होगा।
(c) यह किसी भी खेल महाविद्यालय को संबद्ध नहीं करेगा।
(d) यह केवल शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण तक सीमित रहेगा।

उत्तर: (b)
व्याख्या: इस विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा। यह खेल महाविद्यालयों, खेल अकादमियों और संबंधित संस्थानों को संबद्ध भी करेगा। इसका कार्य केवल शारीरिक शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खेल विज्ञान, प्रशिक्षण, चिकित्सा, प्रबंधन, प्रौद्योगिकी और खेल कॅरियर से जुड़े अन्य विशिष्ट क्षेत्रों में भी कार्य करेगा।

3. राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में कितने स्थायी खेल प्रशिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव है?
(a) 50
(b) 100
(c) 150
(d) 700

उत्तर: (c)
व्याख्या: सरकार ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में लगभग 150 स्थायी खेल प्रशिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव रखा है। इसके अतिरिक्त 700 प्रशिक्षकों को अस्थायी आधार पर भी लगाया जाएगा। यह कदम खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने और राजस्थान की खेल तैयारी तथा खेल अवसंरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है

RASonly

Mission Hariyalo Rajasthan and 10 crore plantation target in the Monsoon 2026.

Under business Mission Hariyalo Rajasthan, a large-scale State project set at raising green cover and enhancing ecological balance, Rajasthan has set a target of 10 crore plantation in Monsoon 2026. The mission has established an extended objective of 50 crore plantation by 2024-2028. To have a timely planning and execution all the departments were coordinated through a coordination meeting with the Additional Chief Secretary, Forest, in the chair. It is anticipated that the campaign would contribute to the enhancement of environmental conservation, mitigate the impact of climate change and increase the number of people involved in plantation activities. The government is also putting together an organized monitoring regime, a pre-determined time scale and coordination of departments to transform the programme into a mass movement.

Key Features of the Mission

- Rajasthan has already fixed a goal of 10 crore plantation of Monsoon 2026.
- Under the Mission Hariyalo Rajasthan, the State will achieve the goal of planting off 50 crore by 2024 to 2028.
- The mission will enhance the green cover, environmental balance and also minimize climate change impacts.
- Nodal officers at the State-level have been requested to be appointed by all the stakeholder departments.
- Departments too have been instructed to prepare the targets of the districts as per the newly constituted districts.

RASonly

- Action plans are to be prepared in details in coordination with District Collectors.

The fourth is the involvement of the people and administrative support.

Public Involvement

- The plantation drive will be interconnected with the public participation.
- Activation of the role of departments, local bodies, educational institutions, and voluntary organisations will be guaranteed.
- The goal of the government in creating the campaign is to make it a mass popular movement.

Three-Tier Task Force System

In order to control the programme, a three-layer task force system has been developed:

- State level: Task Force of the Chief Secretary.
- District level: Task Force at the request of the District Collector
- Sub-divisional level: Task Force of the Sub-Divisional Officer.

The timeline of Plantation Programme is as follows.

The implementation has been pre-determined:

- By 31 March 2026: 2026: Site selection of plantations.
- April- June 2026: pits, fencing, and other preliminary work.
- 15 June-15 July 2026: Purchase of nursery plants.
- 1 July -September 2026: statewide plantation.

The Preparation and monitoring of the nursery are done by the nurse.

- Nurseries of forest department are getting ready with approximately 626.10 lakh plants in 202627.
- There are another 200 lakh plants which are ready to be planted on the forest land.
- As a directive, all departments have been instructed to provide information about the plantations frequently in the Hariyalo App.
- The aim of this digital reporting system is to have an effective monitoring of the programme.

RASonly

Past performance in the past years.

The State government emphasized the success of the previous plantation drives:

- Under the Chief Minister Tree Plantation Mega Campaign in 2024, out of the target figure of 7 crore, 7.22 crore saplings were planted in Rajasthan.
- In the year 2025, the State had a target of 10 crore, but in the course of the year, it realized a surpassed 11.74 crore plantation in the Monsoon season.
- In the case of 2026-27, the target has been assigned to various departments as follows; plantation of 10 crore.

Importance for Rajasthan

Environmental Importance

- The mission will allow expanding the green cover of Rajasthan on a mass level.
- It can help to stabilize the ecological situation and enhance the environmental stability.
- It is also relevant when it comes to mitigation of climate change.

Governance Importance

- Inter-departmental co-ordination and organized implementation is reflected in the mission.
- An administrative model, which is founded on accountability, is exhibited in the use of district-wide planning, the use of task forces and the monitoring through the use of app.
- Social engagement by the population makes the mission have more social foundation and sustainability.

Conclusion

Hariyalo Rajasthan is an initiative that has become significant in both environmental and governance concern of the State. The mission, which has an ecological objective coupled with the administrative planning and citizen involvement, is targeting to achieve 10 crore plantation in Monsoon 2026 and 50 crore plantation by 2028. Its success can go a long way in enhancing the green development plan of Rajasthan.

MCQs (RAS Prelims)

1. What is the plantation target that Rajasthan has fixed by Mission Hariyalo Rajasthan during Monsoon 2026?

RASonly

(a) 5 crore

(b) 7 crore

(c) 10 crore

(d) 50 crore

Answer: (c)

Explanation : The State has established 10 crore plantation as a target under the Mission Hariyalo Rajasthan during the Monsoon of 2026. This target is an extension of a broader long-term initiative of augmenting green cover in Rajasthan and enhancing ecological balance by organizing plantation activities at the departmental and interdepartmental as well as district level.

2. Which among the following best indicates the long-term goal of the Mission Hariyalo Rajasthan?

(a) 25 crore plantation from 2025 to 2030

(b) 50 crore plantation from 2024 to 2028

(c) 10 crore plantation from 2024 to 2026

(d) 100 crore plantation by 2030

Answer: (b)

Explanation: The target of plantation has been declared as 50 crore by Mission Hariyalo Rajasthan in the procession between 2024 and 2028. This larger mission is the 10 crore plantation goal of Monsoon 2026. The programme is aimed at a multi-year environmental programme that involves administrative coordination and the participation of the people.

3. As a part of the three-tier monitoring mechanism of Mission Hariyalo Rajasthan, who shall head the task force at the district level?

(a) Chief Secretary

(b) Conservator of Forests

(c) Sub-Divisional Officer

(d) District Collector

Answer: (d)

Explanation : The district-level task force of the district under Mission Hariyalo Rajasthan will work under the leadership of the District Collector. The three level arrangement involves the Chief Secretary in State level, the District Collector in the

RASonly

district level, and the Sub-Divisional Officer in the sub-divisional level to ensure proper monitoring and implementation.

मिशन हरियालो राजस्थान और मानसून 2026 में 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य।

मिशन **हरियालो राजस्थान** के अंतर्गत, जो हरित आवरण बढ़ाने और पारिस्थितिक संतुलन को सुदृढ़ करने वाला एक व्यापक राज्य स्तरीय अभियान है, राजस्थान ने **मानसून 2026** के लिए **10 करोड़ पौधारोपण** का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस मिशन का व्यापक उद्देश्य **2024 से 2028** के बीच कुल **50 करोड़ पौधारोपण** करना है। समयबद्ध योजना और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बैठक आयोजित की गई। इस अभियान से पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में सहायता मिलेगी और पौधारोपण गतिविधियों में जनभागीदारी भी बढ़ेगी। सरकार इस कार्यक्रम को जनआंदोलन का रूप देने के लिए संगठित निगरानी व्यवस्था, निर्धारित समय-सीमा और विभागीय समन्वय की तैयारी कर रही है।

मिशन की प्रमुख विशेषताएँ

- राजस्थान ने **मानसून 2026** के लिए **10 करोड़ पौधारोपण** का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत राज्य ने **2024 से 2028** तक **50 करोड़ पौधारोपण** का लक्ष्य रखा है।
- इस मिशन का उद्देश्य **हरित आवरण बढ़ाना**, **पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना** तथा **जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना** है।
- सभी सहभागी विभागों को **राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी** नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
- विभागों को नवगठित जिलों के अनुसार **जिलावार लक्ष्य** तय करने के लिए भी कहा गया है।
- **जिला कलेक्टरों** के साथ समन्वय स्थापित कर **विस्तृत कार्ययोजना** तैयार की जाएगी।

जनभागीदारी और प्रशासनिक समन्वय

जनसहभागिता

- पौधारोपण अभियान को **जनभागीदारी** से जोड़ा जाएगा।
- **विभिन्न विभागों, स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थानों और स्वयंसेवी संगठनों** की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जाएगी।
- सरकार का उद्देश्य इस अभियान को एक **व्यापक जनआंदोलन** के रूप में विकसित करना है।

त्रिस्तरीय कार्यबल व्यवस्था

कार्यक्रम की निगरानी के लिए **तीन-स्तरीय कार्यबल व्यवस्था** बनाई गई है:

RASonly

- **राज्य स्तर: मुख्य सचिव** की अध्यक्षता में कार्यबल
- **जिला स्तर: जिला कलेक्टर** की अध्यक्षता में कार्यबल
- **उपखण्ड स्तर: उपखण्ड अधिकारी** की अध्यक्षता में कार्यबल

पौधारोपण कार्यक्रम की समय-सीमा

कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत समय-सीमा निर्धारित की गई है:

- **31 मार्च 2026 तक:** पौधारोपण स्थलों का चयन
- **अप्रैल से जून 2026 तक:** गड्ढे खोदना, फेंसिंग और अन्य प्रारम्भिक तैयारियाँ
- **15 जून से 15 जुलाई 2026 तक:** नर्सरियों से पौधों की खरीद
- **1 जुलाई से सितम्बर 2026 तक:** राज्यभर में व्यापक स्तर पर पौधारोपण

नर्सरी तैयारी और निगरानी

- वन विभाग की नर्सरियों में **2026-27** के लिए लगभग **626.10 लाख पौधों** की तैयारी की जा रही है।
- वन भूमि पर पौधारोपण के लिए अतिरिक्त **200 लाख पौधे** भी तैयार किए जा रहे हैं।
- सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पौधारोपण संबंधी जानकारी नियमित रूप से **हरियालो अनुप्रयोग** पर अपलोड करें।
- इस डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य कार्यक्रम की **प्रभावी निगरानी** सुनिश्चित करना है।

पूर्व वर्षों का प्रदर्शन

राज्य सरकार ने पिछले पौधारोपण अभियानों की उपलब्धियों को रेखांकित किया:

- **मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान 2024** में **7 करोड़** के लक्ष्य के विरुद्ध **7.22 करोड़ पौधे** लगाए गए।
- **मानसून 2025** में **10 करोड़** के लक्ष्य के मुकाबले **11.74 करोड़ से अधिक पौधारोपण** किया गया।
- **2026-27** के लिए विभिन्न विभागों को कुल **10 करोड़ पौधारोपण** का लक्ष्य आवंटित किया गया है।

राजस्थान के लिए महत्त्व

पर्यावरणीय महत्त्व

- यह मिशन राजस्थान में बड़े पैमाने पर **हरित आवरण बढ़ाने** में सहायक हो सकता है।
- इससे **पारिस्थितिक संतुलन** मजबूत होगा और पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार आएगा।
- यह **जलवायु परिवर्तन शमन** की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

RASonly

प्रशासनिक महत्त्व

- यह मिशन **अंतर-विभागीय समन्वय** और **संगठित क्रियान्वयन** का उदाहरण प्रस्तुत करता है।
- **जिलावार योजना**, **कार्यबल व्यवस्था** और **अनुप्रयोग आधारित निगरानी** प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करती है।
- जनभागीदारी इस मिशन को सामाजिक आधार और दीर्घकालिक स्थायित्व प्रदान करती है।

निष्कर्ष

मिशन **हरियालो राजस्थान** राज्य के पर्यावरणीय और प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक महत्त्वपूर्ण पहल बनकर उभरा है। **मानसून 2026** में **10 करोड़ पौधारोपण** और **2028 तक 50 करोड़ पौधारोपण** के लक्ष्य के साथ यह मिशन पर्यावरणीय उद्देश्यों को प्रशासनिक योजना और नागरिक सहभागिता से जोड़ता है। इसकी सफलता राजस्थान की हरित विकास रणनीति को अत्यंत सशक्त बना सकती है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत मानसून 2026 के लिए राजस्थान ने कितना पौधारोपण लक्ष्य निर्धारित किया है?
(a) 5 करोड़
(b) 7 करोड़
(c) 10 करोड़
(d) 50 करोड़

उत्तर: (c)
व्याख्या: मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत राज्य ने मानसून 2026 के लिए **10 करोड़ पौधारोपण** का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य राजस्थान में हरित आवरण बढ़ाने, पारिस्थितिक संतुलन मजबूत करने और विभागीय तथा जिलास्तरीय समन्वित प्रयासों के माध्यम से बड़े पैमाने पर पौधारोपण को सफल बनाने की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है।

2. निम्नलिखित में से कौन-सा मिशन हरियालो राजस्थान के दीर्घकालिक लक्ष्य को सही रूप में दर्शाता है?
(a) 2025 से 2030 तक 25 करोड़ पौधारोपण
(b) 2024 से 2028 तक 50 करोड़ पौधारोपण
(c) 2024 से 2026 तक 10 करोड़ पौधारोपण
(d) 2030 तक 100 करोड़ पौधारोपण

उत्तर: (b)
व्याख्या: मिशन हरियालो राजस्थान ने **2024 से 2028** की अवधि के लिए कुल **50 करोड़ पौधारोपण** का लक्ष्य निर्धारित किया है। मानसून 2026 का 10 करोड़ पौधारोपण लक्ष्य इसी व्यापक योजना का हिस्सा है। यह कार्यक्रम बहुवर्षीय पर्यावरणीय अभियान है, जिसमें प्रशासनिक समन्वय और जनभागीदारी दोनों को महत्त्व दिया गया है।

RASonly

3. मिशन हरियालो राजस्थान की त्रिस्तरीय निगरानी व्यवस्था में जिला स्तर के कार्यबल की अध्यक्षता कौन करेगा?

(a) मुख्य सचिव
(b) वन संरक्षक
(c) उपखण्ड अधिकारी
(d) जिला कलेक्टर

उत्तर: (d)
व्याख्या: मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत जिला स्तर का कार्यबल **जिला कलेक्टर** की अध्यक्षता में कार्य करेगा। त्रिस्तरीय व्यवस्था में राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर और उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी जिम्मेदारी निभाएंगे, जिससे कार्यक्रम की प्रभावी निगरानी और क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

RASonly